

प्रेषक,

एस0 के0 मुट्टू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून:दिनांक: 2 / जून, 2010

विषय:-ग्राम शुक्लापुर ई0हो0टा0, तहसील विकास नगर, जिला देहरादून में हिमालयन इन्वायरमेन्टल आर्गनाइजेशन (हैस्को) को जल संसाधनों के चिन्हीकरण हेतु, आइसोटोप हाइड्रोलोजी की स्थापना हेतु कुल 0.117 है0 भूमि पट्टे पर आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या-2075/12 ए0-90(2005-2008) डी0एल0आर0सी0, दिनांक-8.9.2008 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, शासनादेश संख्या-258/16(1)/73-रा-1 दिनांक-09.05.1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या-1695/97-1-1(60)/93-रा-1 दिनांक-12.09.1997 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत, एवं पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दी गयी सहमति/अनापत्ति के दृष्टिगत, ग्राम शुक्लापुर ई0हो0टा0, तहसील विकास नगर, जिला देहरादून में हिमालयन इन्वायरमेन्टल आर्गनाइजेशन (हैस्को) को जल संसाधनों के चिन्हीकरण हेतु, आइसोटोप हाइड्रोलोजी की स्थापना हेतु, कुल 0.117 है0 भूमि, प्रचलित बाजार दर के मूल्य की दर की दो गुने दर से निकाले गये भूमि के मूल्य के बराबर नजराना एक मुश्त जमा कराये जाने के अतिरिक्त, नई दरों पर निकाली गयी मालगुजारी के बीस गुने के बराबर धनराशि पंजीकृत मूल्य के रूप में एक मुश्त जमा कराये जाने पर, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन पट्टे पर आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. प्रश्नगत भूमि का उपयोग भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर के साथ संस्था द्वारा हस्ताक्षरित एम0 ओ0 यू0 के अनुरूप प्रयोगशाला तथा सम्बन्धित कार्यों के लिए ही की जायगी, यदि भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर तथा संस्था द्वारा यह कार्य नहीं किया जाता है या किसी अन्य कारण से भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर इस योजना पर कार्य नहीं करता है, तब लीज निरस्त समझी जायगी।
2. प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
3. प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या- 150/1/85(24)-रा-6 दिनांक-09 अक्टूबर, 1987

में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नहीं होगा।

4. प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नहीं रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
5. यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।
6. प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
7. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दुसंख्या-1 से 6 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

- 2- उक्त आदेशों का नियमानुसार तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए, शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में, जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की एक प्रति यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0के0मुट्टू)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0सं0- 1269/समदिनांकित/2010

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. श्री अनिल पी0 जोशी, हैस्को ग्राम शुक्लापुर, पो0 आ0 अम्बीवाला, वाया प्रेमनगर, जिला देहरादून।
5. निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
6. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।